regime they should have.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Mr. Chairman, Sir, the plight of 32,000 Indians in Afghanistan is similar to the NRIs during the invasion of Kuwait. We know that the U.N. Humanitarian Relief Fund has compensated Indian nationals. May I know from the hon. Minister whether this case has been taken up by the Government with the U.N. Humanitarian Relief Fund to compensate them because they have lost all their business and livelihood in that country? Has the Government taken up strongly to see that they are compensated by the U.N. Humasnitarian Relief Fund?

SHRI I.K. GUJRAL: I think, the context which my hon. friend has mentioned is, if I may use the word without any disrespect, 'quite far fetching' Kuwait was a situation of war, one country ran over the other and then what happened, I am not going to comment on that. The situation here is very different. Some sort of a civil war is going on, if I may use that word because, I think, Talibans are sponsored from outside the country. Some sort of militancy is trying to destablise the whole country. Therefore, for the U.N. to come and start compensating those who have come out, I think, at the moment, is not very right. I do hope that as the situation improves, a ligitimate Government comes to office—I am sorry, I must correct that, they are in office—and the legitimate Government will be able to assert more decisively and, perhaps, at that time we can think of compensation.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Part (a) of my question is this: Is the Minister or the External Affairs Ministry in touch with the International Red Cross to find out the position with regard to the people of Indian origin? Part (b) of my question is, a conference or a meeting was held in Iran to discuss the matter relating to Afghanistan and it was attended by the External Affairs Secretary also. Was the question of ill treatment or the said plight of the Indian nationals or the people of Indian origin taken up in that particular conference?

SHRI I.K. GUJRAL: Sir, twc confernces have been held—one was in Tehran and another United Nations-sponsored conference was in New York. The third was to be held in Peshawar to discuss precisely this type of issues. That conference was cancelled or postponed for the time being because Pakistan did not agree that India should be invited to that conference being held in Peshawar. We are now thinking or hoping that the third conference which is going to look at the humanitarin dimension of it, will be held soon. India has already taken interest in that and India will go there.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Have you received any report from the International Red Cross?

SHRI I.K. GUJRAL: The organisation which is looking after this is a UN organisation of refugees. At the moment 18,000 Afghans who are in India are registered with it. I am of the impression that they are getting stipend or whatever other things.

Telephones disconnected without Notice

*386. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether many telephone connections are disconnected without ensuring the receipt of notices to the subscribers due to non-payment of bills which are not sent to them on their correct addresses especially in transfer cases;

(b) if so, whether some connections transferred from R.K. Puram to Vasant Vihar, have not been shown as transferred in official records and bills are being issued in the names of former subscribers even after lapse of 10 months with connections being disconnected without the congnizance of subscribers;

(c) if so, the details of such cases; and

(d) if so, the action taken against MTNL and by when these are likely to be connected?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बिना नोटिस दिए काटे गए टेलीफोन कनेक्शन

(क) निर्धारित पद्धति के अनुरूप, उपभोक्ताओं को टेलीफोन बिल बताए गए पते पर भेजे जाते हैं। पद्धति में यह भी निर्धारित है कि बिलों का भुगतान न किए जाने पर पहले, उपभोक्ता को फोन पर याद दिलाया जाना चाहिए और फिर पंजीकृत डाक से उसका अनुस्मारक भेजा जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से जुड़े उपभोक्ताओं के मामलों में, सबसे पहले 15 दिन के लिए जावक कॉल सुविधा समाप्त की जानी होती है और इस दौरान फोन पर डायल टोन के बयाज बिल का भुगतान न किए जाने संबंधी पहले से रिकार्ड घोषणा होती है। ऐसे मामलों में कोई पंजीकृत अनुस्मारक नहीं भेजा जाता। तथापि, अनजाने में भूल से गलत कनेक्शन काटे जाने का कोई एकाध मामला हो सकता है।

(ख) से (घ) एक ऐसा मामला एम टी एन एल प्राधिकारियों की जानकारी में आया है जिन्होंने उस पर उपचारात्मक कार्रवाई की है। यह मामला टेलीफोन नम्बर 6871104 से संबंधित है जिसमें पते में परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया था जिसके कारण उक्त टेलीफोन कनेक्शन काट दिया गया। अब यह गलती सुधार दी गई है और टेलीफोन को 2.12.96 को पुनः चालू कर दिया गया है। अधिकाधिक सावधानी बरतने की दृष्टि से, एम टी एन एल प्राधिकारियों को इस मामले की भली भांति समीक्षा करने और सरकार को इस आशय की जानकारी देने के लिए कहा गया है कि इस क्षेत्र में इस तरह के अन्य कोई और मामले तो नहीं हैं। एम टी एन एल प्राधिकारियों को इस मामले की जांच करने और संबंधित व्यक्तियों की ओर से लापरवाही, यदि कोई हो, बरतने पर उपयुक्त कार्रवाई करने के अनुदेश भी दिए गए हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि आपका जो उत्तर यहां दिया गया है वैसे तो काफी संतोषजनक है जैसा होना चाहिए, लेकिन जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया है वह व्यवहार में नहीं आता है। उन्होंने ऐसा बता दिया है कि इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जुड़े हुए उपभोक्ताओं को सूचना दे दी जाती है और यह रेकार्डेड है। रेकार्डेड डायल टोन पर आ जाता है कि आपका टेलीफोन किसलिए काटा गया है, किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। यहां तो एक के बारे में कहा गया है लेकिन ऐसे बहुत से केसेज़ हैं। माननीय मंत्री जी से मैं अपना पहला पूरक प्रश्न यह पूछना चाहूंगी कि क्या सभी के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म बनायेंगे? दूसरा क्या आप महानगर टेलीफोन के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाकर ऐसा कोई निर्देश देंगे कि फिर ऐसी गलतियां अनजाने में न हों, जो आप लिख रहे हैं कि अनजाने में भूल से काट दिए जाते हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमान्, जो माननीय सदस्या ने प्रश्न किया है, अधिकारियों को निर्देश हमने पहले ही दे दिए हैं और हम उसकी फिर पुनरावृत्ति कर देंगे। उन्होंने जो बिल के बारे में यहां पर प्रश्न उठाया है कि यें शिकायतें अकसर मिलती रहती हैं। इसलिए कल ही हमने इस बात पर अधिकारियों के बीच में विचार किया है कि एक ऐसा इंतजाम किया जाए कि जिसका टेलीफोन बिल पेंडिंग हो और टेलीफोन उसका कटने वाला हो, जब वह टेलीफोन उठाए तो टेप रिकार्ड में उसको यह सुनाई पड़े कि आपका नाम नान-पेमेंट में टेलीफोन कनैक्शन डिस्कनैक्ट कर दिया गया है। जिससे वह समय पर अपने टेलीफोन बिल को जमा कर ले। इस तरह की व्यवस्था पर कल हमने विचार-विमर्श किया है और अधिकारियों ने हमें विश्वास दिलाया है कि इस तरह की व्यवस्था हम कर लेंगे।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह मैं सैकण्ड सप्लीमेंटरी पूछना चाहूंगी कि उपभोक्ताओं को निर्देश मिलता है कि वे यदि उन्हें बिल नहीं मिला तो वे आएं और अपना बिल खुद कलैक्ट करें। क्या यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे बिल जाकर कलैक्ट करें?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: सभापति महोदय, यह विभाग की जिम्मेदारी है कि बिल की सूचना उनको दे और इसको हम सुनिश्चित करेंगे कि विभाग अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी से इसका अनुपालन करे।

श्री जलालुदीन अंसारी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आम उपभोक्ता को क्या मिलता है वह अलग सवाल है। अभी हमारी बगल में माननीय सांसद् श्री नगेन्द्र नाथ ओझा बैठे हुए हैं। यह 8 महीना हो गया अभी तक इनके घर पर फोन नहीं लगाया गया है, अपने क्षेत्र के अंदर उनका जो घर है, कंस्टीटूएंसी टेलीफोन अभी तक नहीं लगा है 7-8 महीना हो गया। हम माननीय मंत्री जी

से जानना चाहेंगे कि अगर इसी तरह से इनका काम चलता रहेगा तो आम उपभोक्ता का क्या होगा? इसीलिए मंत्री जी बताएं कि नगेन्द्र नाथ ओझा जो सांसद् हैं उनकी कंस्टीटूएंसी जो गांव में है, विलेज में है, 8-9 महीना हो गया है अभी तक फोन नहीं लगा है?

†[ ]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: माननीय सभापति महोदय, इसको हम विशेष रूप से दिखवा लेंगे और हमारा प्रयास होगा कि यह शिकायत जल्दी दूर हो जाए।

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Demand for Releasing further Cotton Quota for Export

*384. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAIPATEL:
SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAIPATEL:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there is a demand from the cotton producing states for releasing further cotton quota for export in order to ensure reasonable price to the farmers;

(b) whether it is a fact that the meeting of the Cotton Advisor Board held in November, 1996 to review the supply and demand position in this regard;

(c) if so, the outcome thereof; and

(d) to what extent quota of cotton for export from Gujarat has further enhanced for the current year?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) to (d) Demands are received from various cotton producing States, from time to time, for release of quota of cotton for export.

No meeting of the Cotton Advisory Board was held in November, 1996.

During the 1996-97 season, the Gujarat State Cooperative Cotton Federation Ltd. has been allotted an export quota of 50,000 bales of cotton on 7-10-96. Further allocation would be considered after taking into account all relevant factors, including estimates of production, domestic demand and likely surplus.

Tax evasion in sale of Cielo cars

*387. SHRI SANJAY NIRUPAM:
SHRI O. P. KOHLI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news report about a Rs. 25 crore tax evasion in sale of Cielo cars;